



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

|          |  |
|----------|--|
| सं. 208] | नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 17, 2019/आषाढ़ 26, 1941     |
| No. 208] | NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 17, 2019/ASHADHA 26, 1941 |

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**

**(वाणिज्य विभाग)**

**(व्यापार उपचार महानिदेशालय)**

**जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना**

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2019

**मामला सं. एसएसआर 04/2019**

**विषय - चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित शीट ग्लास के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा की शुरुआत।**

**फा.सं. 7/10/2019-डी जी टी आर.**—वर्ष 1995 और इसके पश्चात भी यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे यहां इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण एवं क्षति के निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 (जिसे यहां इसके बाद नियमावली भी कहा गया है), के संबंध में, निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें यहां इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) ने चीन जनवादी गणराज्य (जिसे यहां इसके पश्चात संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “शीट ग्लास” (जिसे यहां इसके पश्चात संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू करने की सिफारिश की है। प्राधिकारी ने अपने अंतिम जांच परिणाम संख्या 14/22/2013-डी जी ए डी दिनांक 19.12.2014 के अनुसार संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्कों को लागू करने की सिफारिश की है। केन्द्रीय सरकार द्वारा सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 07/2015-सीमाशुल्क (ए डी डी) दिनांक 13.03.2015 के अनुसार शुल्क लागू किए गए थे।

2. और जबकि, संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना का आरोप का आरोप लगाते हुए, शुल्कों को और पांच वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने के लिए

संबद्ध वस्तुओं के आयात पर प्रवृत्त पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की शुरुआत की मांग करते हुए, अधिनियम और नियमों के अनुसरण में मै. एमर्ज ग्लास इंडिया प्रा. लि. (जिन्हें यहां इसके बाद “याचिकाकर्ता” कहा गया है) द्वारा याचिका दायर की गई है।

#### क. विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद (“शीट ग्लास” “संबद्ध वस्तु अथवा “विचाराधीन उत्पाद”) है।
4. शीट ग्लास का उत्पादन क्षैतिक रूप से “लेहर” का प्रयोग करके किया जाता है। ग्लास को पिछली सामग्री की मुक्त सतह से सीधे लिया जाता है और शीट के किनारों का घुमावदार ढांचे का उपयोग कर कांच को ऊपर की ओर चलाकर स्थिर किया जाता है। जब पिघले हुए कांच को ग्लास फर्नेस से लगभग 1000 मि. मी. की ऊंचाई पर एक वर्टिकल ड्राइंग की ओर भेजा जाता है तो गठित ग्लास हॉरीजॉन्टल प्रवाह द्वारा एक ग्लास शीट में बदल जाता है। एक बार शीट के बन जाने के पश्चात इसे एक पॉलिश किए गए सेल में मोड़ा जाता है और हॉरीजॉन्टल रूप से एक लेहर में ले जाया जाता है। शीट ग्लास की उत्पादन प्रक्रिया पूरी तरह से फ्लोट ग्लास की उत्पादन प्रक्रिया से बिल्कुल भिन्न है जहां एक ग्लास शीट को मोल्टेन मैटल, विशेष रूप से टिन, की सतह पर फ्लोटिंग मोल्टेन ग्लास द्वारा निर्मित किया जाता है। यह प्रक्रिया शीट को समान मोटाई और अत्यधिक समतल सतह प्रदान करती है।
5. वर्तमान याचिका निर्णायक समीक्षा जांच के लिए होने के कारण, निर्धारित न्याय शास्त्र और प्राधिकारी के पिछले अनुभवों के अनुसार, विचाराधीन उत्पाद वही बना रहा है जैसाकि मूल अधिसूचना में परिभाषित किया गया है।
6. संबद्ध उत्पादों को अध्याय शीर्ष 70 “ग्लास और ग्लास वेयर” के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। संबद्ध वस्तुओं को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के विभिन्न उप शीर्षों जैसे 7003 12, 7003 19, 7003 30, 7004 20, 7004 90, 7005 10, 7005 21, 7005 29, 7005 30, 7009 10, 7009 91, 7011 90 के तहत आयात किया जा रहा है। किसी भी स्थिति में सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक प्रयोजनों के लिए है और वस्तुओं का वर्णन शुल्कों के अधिरोपण और संग्रहण के लिए परिचायक रहेगा।

#### ख. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

7. निर्णायक समीक्षा के अनुरोध मै. एमर्ज ग्लास इंडिया प्रा.लि. द्वारा दायर किया गया है जो कुल घरेलू उत्पादन में लगभग 77 प्रतिशत हिस्से के लिए उत्तरदायी है। भारत में संबद्ध वस्तुओं के एक और उत्पादक हैं अर्थात् मै. भारत ग्लास ट्यूब्स लिमिटेड (बी जी टी एल), जिनका कुल घरेलू उत्पादन में लगभग 23 प्रतिशत हिस्सा है, जो याचिका का पूरी तरह से समर्थन करते हैं।
8. प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता का कुल घरेलू उत्पादन में 77 प्रतिशत हिस्सा बनता है और याचिकाकर्ता समर्थन सहित देश में कुल घरेलू उत्पादन में 100 प्रतिशत हिस्से के लिए उत्तरदायी हैं। इसीलिए, याचिकाकर्ता को नियम 2(ख) की शर्तों में एक पात्र घरेलू उद्योग माना गया है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता नियम 5(ख) के तहत मत परीक्षण में भी सफल हुआ है।

#### ग. शामिल देश

9. वर्तमान याचिका एक निर्णायक समीक्षा जांच होने के कारण, संबद्ध देशों का क्षेत्र मूल जांच होने के कारण, संबद्ध देशों का क्षेत्र मूल जांच में संबद्ध तक सीमित है इसलिए, वर्तमान याचिका चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित वस्तुओं के विरुद्ध है।

#### घ. प्रक्रिया

10. समीक्षा में संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लागू करने की सिफारिश करते हुए अंतिम जांच परिणाम संबंधी अधिसूचना के सभी पहलू शामिल होंगे।
11. संबंधित नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और नियम 20 के उपबंध आवश्यक संशोधनों के साथ लागू होंगे।

**ड. जांच की अवधि (पी ओ आई)**

12. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, जांच की अवधि अप्रैल, 2018-मार्च, 2019 है। क्षति जांच अवधि में 2015-16, 2016-17, 2017-18 और जांच की अवधि शामिल होगी। जांच अवधि के बाद की अवधि पर भी संभावित विश्लेषण के प्रयोजनार्थ विचार किया जा सकता है।

**च. सूचना प्रस्तुत करना**

13. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देशों की सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु के आयातकों व प्रयोक्ताओं को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना निम्नलिखित को प्रस्तुत करने और प्राधिकारी को अपने विचारों से अवगत कराने का अलग से अनुरोध किया गया है:

भारत सरकार

व्यापार उपचार महानिदेशालय

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

5, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

**छ. समय-सीमा**

14. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (दिनों 40) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजा जाना चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, रिकॉर्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

15. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हितों की प्रकृति सहित) सूचित करें और अपने प्रश्नावली के उत्तर दायर करें तथा इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिन (40 दिन) के भीतर घरेलू उद्योग के आवेदन पत्र पर अपनी टिप्पणियां दें। यह सूचना हार्ड कॉपी तथा सॉफ्ट कॉपी में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

**ज. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

16. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख). अगोपनीय रूप में अंकित दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए।
17. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां प्रस्तुत करना जरूरी होगा।
18. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए, सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।

19. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध/ रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।
  20. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
  21. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।
- झ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**
22. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।
  23. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

डॉ. सुनील कुमार, अपर सचिव एवं महानिदेशक

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

### INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 2019

Case No. SSR- 04/2019

**Subject: Initiation of Sunset review of Anti-Dumping investigation concerning imports of Sheet Glass originating in or exported from China PR.**

**F.No. 7/10/2019-DGTR.**—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and thereafter (hereinafter also referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred as the Rules), the Designated Authority (hereinafter referred to as Authority) recommended imposition of Anti-Dumping Duty on imports of "Sheet Glass", (hereinafter also referred to as subject goods) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as subject country). The Authority vide its final findings No.14/22/2013-DGAD dated 19.12.2014 recommended imposition of anti-dumping duties against dumped imports of the subject goods from the subject country. Duties were imposed by the Central Government vide Customs Notification No. 07/2015- Customs (ADD) dated 13.03.2015.

2. And whereas, a petition has been filed by M/s Emerge Glass India Pvt. Ltd. (hereinafter referred to as 'petitioners') in accordance with the Act and the Rules, seeking initiation of sunset review of the Anti-dumping duty in force on import of subject goods for extending the duties for a further period of five years, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury of the subject goods originating in or exported from subject country.

**A. Product under Consideration**

3. The product under consideration for the purpose of present investigation is “Sheet Glass” the “subject goods” or the “Product under Consideration”).
4. Sheet Glass is produced by using horizontally lehr. The glass is taken directly from the free surface of the melt and the edges of the sheet are stabilized by driving the glass upward using rotating bodies. Once the molten glass passes from the glass furnace to a vertical drawing machine to a height of about 1000 MM from where the formed glass is converted in to glass sheet by horizontal flow. Once the sheet has been formed it is bent over a polished metal roll and is carried away horizontally into a lehr. Sheet glass production process is completely different from that of Float glass where a sheet of glass is made by floating molten glass on a bed of molten metal, typically tin. This method gives the sheet uniform thickness and extremely flat surfaces.
5. The present petition being for sunset review investigation, as per the settled jurisprudence and the past practices of the Authority, the Product under Consideration remains the same as defined in the original notification.
6. The subject products are classified under Chapter Heading 70 “Glass and glassware”. The subject goods are being imported under various sub-headings like 7003 12, 7003 19, 7003 30, 7004 20, 7004 90, 7005 10, 7005 21, 7005 29, 7005 30, 7009 10, 7009 91, 7011 90 etc. of the Customs Tariff Act, 1975. In any case, the customs classification is for indicative purposes only and the description of goods shall prevail for the imposition and collection of duties.

**B. Domestic Industry & Standing**

7. The request for the sunset review has been filed by M/s Emerge Glass India Pvt. Ltd. who accounts for almost 77% share in the total domestic production. There is one more producer of the subject goods in India namely M/s. Bharat Glass Tubes Limited (BGTL) having around 23% share in the total domestic production which has duly supported the petition.
8. The Authority notes that the petitioners hold 77% share in total domestic production and the petitioner along with the supporter accounts for 100% share in the total domestic production in the country. Therefore, the petitioners can be termed as eligible Domestic Industry in terms of the Rule 2(b). Further, the petitioner also passes the test of standing under Rule 5(b).

**C. Country Involved**

9. The present petition being a sunset review investigation, the scope of the subject countries is confined to the subject country in the original investigation. Therefore, the present petition is against the goods originating in or exported from China PR.

**D. Procedure**

10. The review will cover all aspects of Final Finding Notification No.14/22/2013-DGAD dated 19.12.2014 recommending imposition of anti-dumping duty on import of subject goods originating in or exported from subject country.
11. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rule shall be mutatis mutandis applicable in this review.

**E. Period of Investigation (POI)**

12. The period of investigation for the purpose of the present investigations is April 2018-March 2019. The injury investigation period shall cover the periods 2015-16, 2016-17, 2017-18 and the period of investigation. The period after the investigation period may also be considered for the purpose of likelihood analysis.

**F. Submission of information**

13. The known exporters in the subject countries, the Government of the subject countries through their embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

**The Designated Authority,  
Directorate General of Trade Remedies,  
Ministry of Commerce & Industry,  
Department of Commerce  
4th Floor, Jeevan Tara Building,  
5, Parliament Street, New Delhi -110001.**

**G. Submission of Information**

14. Any information relating to the present investigation and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-Dumping Rules.

15. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the Antidumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

#### **H. Submission of Information on Non-Confidential basis**

16. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/ submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.
17. Information supplied without any confidential marking shall be treated as nonconfidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and two (02) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.
18. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.
19. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
20. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
21. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

#### **I Inspection of Public File**

22. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties. Non-cooperation

23. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Director General